an>

Title: Need for formulate a policy to promote traditional handicrafts of border districts of Uttarakhand.

**डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उन सैंकड़ों गांवों की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो सीमाओं पर हैं और जहां से तेजी से लगातार पलायन हो रहा है। चिन्ता का विषय यह है कि जहां पलायन होगा, राष्ट्र के प्रहरी की तरह सीमाओं पर बसे गांव हैं। यह राष्ट्र के लिए संकट का विषय होगा। उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो भेड़ पालन करते थे, उनकी आर्थिकी धीरे-धीरे कमजोर होने के कारण सक्षम लोग पलायन कर गए और जिन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, वे पलायन करने पर मजबूर हैं। जो ऊनी भेड़ पालन, बकरी पालन होता था, जो भी कारम रहे होंगे, चाहे वन अधिनियम, चाहे सरकार की खराब नीतियां, वह पूरा क्षेत्र खाली हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे पारंपरिक कुटीर उद्योग खत्म हो रहे हैं। उन्हें संरक्षित करना चाहिए। उन्हें जड़ी-बूटी से जोड़ना चाहिए। कीड़ा जड़ी जो उस क्षेत्र में मिलती है, वह 6 से 8 लाख रुपये किलो है। सरकार विधिवत तरीके से संजीवनी और कीड़ा जड़ी को उन लोगों के साथ जोड़कर उसका कृषिकरण करते हुए उनकी आर्थिकी को मजबूत करे। इससे दोनों काम होंगे, वे मजबूत होंगे और सीमाओं की रक्षा भी होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चाहे नेपाल का बार्डर हो या तिब्बत-भारत का बार्डर हो, वर्ष 2004 में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चीन के प्रधान मंत्री से समझौता किया था और वर्ष 2006 में नाथूला दर्रे को व्यापार के लिए खोल दिया था। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं कि इन सीमावर्ती क्षेत्रों से यातायात और व्यापार को खोला जाना चाहिए ताकि वे देश की प्रगति में अपना हिस्सा बखूबी निभा सकें और पलायन से बच सकें।